told them very strongly that they should not interfere in our internal affairs.

SHRI HEM BARUA : He has said that he has told them very strongly that there should be no Chinese activity against the interest and security of this country. But what is the response of China ? That is what we are interested in knowing.

MR. SPEAKER : Mr. Krishna Kumar Chatterji.

SHRI KRISHNA KUMAR CHATTERJI : Is the hon. Minister for External Affairs aware of the fact that, during the mid-term elections in West Bengal, the propaganda machinery of Peking was fully utilised to subvert the democratic process of elections ? Is he also aware of the fact that even the Chinese Embassy in this country was taking active and keen interest to see that the results of the mid-term poll in West Bengal went against the best and real interests of this country ?

SHRI DINESH SINGH : How can I answer this ?

SHRI KRISHNA KUMAR CHATTERJI ; He has not answered my question ...(*Interruption*).

MR. SPEAKER : He is not in a position to answer that.

SHRI SWELL : While everything should be done to safeguard the security of the country, I would like to know whether it is a fact that, following the recent Sino-Soviet conflict in Amur-ussuri area, Peking Radio had been blaring away that the Soviet Union was trying to form an anti-Chinese block, an unholy alliance, along with such countries as Japan, Thailand, Malaysia, Philippines, Indonesia. South Korea and South Vietnam, but have conspicuously left out India from that list. I would like to know whether Government considers this omission as having any significance and whether they consider that it is going to help to promote the idea of the Prime Minister in her New Year foreign policy statement to have talks with China without any pre-condition. May I know whether the Government today, in view of what the Prime Minister has stated, consider it a right policy to view our relation with China in the totality of the emerging Asian and world situation and would resist from being drawn into mutual philippics and tit-for-tat action.

SHRI DINESH SINGH : I entirely agree with the hon. Member that all diplomatic action cannot be taken tit-for-tat. We have to function according to our conditioning and our system of working, and other countries do what they like. But there is a certain measure of reciprocity in this which we try to conform to.

So far as the question of Chinese broadcast is concerned, I do not know the reasons why they have or have not included India On many occasions they have put India and Souiet Union together.

SHRI SWELL ; My main question has not been answered. I wanted to know whether Government considered this omission as significant. This is number one. The second question is whether Government consider it conducive to the promotion of the talk-idea between India and China without pre-condition of which the Prime Minister spoke in her New Year Day message.

SHRI DINESH SINGH : We welcome any change in the Chinese policy and I have already answered the question regarding what the Prime Minister has said. But I cannot say ...(*Interruptions*) whether that omission has any significance or not .. (*Interruption*).

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi) : Why don't you have a class for probationers in this House ?

MR. SPEAKER : The Question Hour is over. Now we take up the Short Notice Question.

SHORT NOTICE QUESTION

अखबारी कागज का समाचारपत्रों को आवंटन

+

SNQ. 4. **श्री मधु लिमये :**

श्री ए० श्रीधरन :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दैनिक समाचारपत्रों को अखबारी

कागज के आवंटन सम्बन्धी सरकार की नीति क्या है,

(ख) क्या चालू वर्ष के लिये अखबारी कागज के 'कोटे' के बारे में निर्णय करते समय तालाबन्दी की अवधि के दौरान कागज की अप्रयुक्त मात्रा को ध्यान में रखा गया है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) 1968-69 में दैनिकों समेत समाचार-पत्रों को अखबारी कागज के आबंटन सम्बन्धी नीति सार्वजनिक सूचना संख्या 55–आई० टी० सी० (पी० एन०) /68, तारीख 5 अप्रैल, 1968 में दी हुई है जिसकी एक प्रति 6 अप्रैल, 1968 को लोक सभा की मेज पर रखी जा चुकी है ।

(ख) और (ग) : 1968-69 के लिए समाचार-पत्रों को अखबारी कागज का कोटा उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना के अनुसार निश्चित किया गया है । उक्त नीति में यह व्यवस्था है कि समाचारपत्र अपनी-अपनी आवश्यकताएं अधिकृत कोटे से ही आवधिकता, पृष्ठ क्षेत्र, पृष्ठ संख्या और प्रचार संख्या में समंजन कर पूरी करें । वर्तमान प्रथा के अनुसार 1968-69 के दौरान समाचार-पत्र की अखबारी कागज की खपत 1968-69 में उसकी वास्तविक स्थिति के आधार पर 1969-70 में निकाली जाएगी और पाई गई अखबारी कागज की अप्रयुक्त मात्रा 1969-70 के लिए उसके कोटे में समंजित की जाएगी ।

श्री मधु लिमये : क्या यह सही है कि पिछले वर्ष तालाबन्दी के कारण जो अखबार बन्द थे, उन्होंने सरकारी जानकारी में अपने बचे हुए कागज को या तो काले बाजार में बेचा और या नये-नये परिशिष्ट या सप्लीमेंट्स निकाल कर खर्च कर डाला ? क्या मन्त्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर गया है कि इन सप्लीमेंट्स में बहुत बड़े पैमाने पर इश्तहार या विज्ञापन छपे हैं और अखबारवालों को काफी आमदनी हुई है ? मन्त्री महोदय इस आमदनी के बारे में सूचना दें । क्या वह बचा हुआ कागज काले बाजार में बेचा गया है और ऐसा उन की अनुमति से या जानकारी में किया गया है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : वह कागज काले बाजार में बेचा गया है, इस की कोई खबर हम लोगों को नहीं है । यह पता लगाना मुश्किल होता है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या ऐसा सरकार या मन्त्री महोदय की अनुमति से किया गया है ।

श्री सत्य नारायण सिंह : क्या हम उन को इस बात की अनुमति देंगे कि वे कागज को ब्लैक मार्केट में बेचें ? यह सवाल पूछने से ऐसा मालूम होता है कि जैसे हम ने कागज को ब्लैक मार्केट में बेचने की अनुमति दे दी ।

श्री मधु लिमये : मैं ने कहा है, "अनुमति से या जानकारी में ।"

श्री सत्य नारायण सिंह : अगर कुछ अखबारों ने अपने बचे हुए कागज से सप्लीमेंट्स निकाले हैं, तो उस में हमारी अनुमति का प्रश्न नहीं है । पालिसी में उन को अधिकार है कि जो कोटा उन्हें मिलता है, उस में वह अपनी पीरियाडिसिटी और पृष्ठों की संख्या आदि को एजस्ट कर सकते हैं । हमारी तरफ से उन्हें रोकने का सवाल नहीं है ।

श्री मधु लिमये : क्या मन्त्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर गया है कि उन अखबारों को विज्ञापनों के जरिये बहुत ज्यादा पैसा मिला है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : सप्लीमेंट में विज्ञापन छपते हैं और विज्ञापनों से पैसा मिलता ही है ।

श्री मधु लिमये : मन्त्री महोदय ने मान लिया है कि उन अखबारों ने काले बाजार में

कागज बेचा होगा। सिर्फ उन की अनुमति से नहीं बेचा है। वह यह भी मानते हैं कि उन्होंने सप्लीमेंट्स में भी कागज खर्च किया और उन्हें पैसा भी मिला है। अखबारों के मालिकों ने वेज बोर्ड की रपट को कार्यान्वित करने से इन्कार किया और तालाबन्दी हुई। जिस रपट को स्वयं सरकार ने कुबूल किया था, उस को भी कार्यान्वित नहीं किया गया, बल्कि मालिकों ने तालाबन्दी का इस्तेमाल किया। मजदूरों को तो वेतन नहीं मिला और तालाबन्दी की अवधि में अखबारों को जो कागज मिला, उस से सप्लीमेंट्स निकाल कर और उन में नये-नये इश्तहार छाप कर मालिक पैसा कमा रहे हैं। क्या मन्त्री महोदय इस बारे में सख्ती से कार्यवाही करेंगे और कर्मचारियों को जो उचित वेतन और दूसरी सुविधायें मिलनी चाहिए, उस को दिलवाने के लिए क्या वह इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे, जो कि अखबारों ने सप्लीमेंट्स में इश्तहार छाप कर कमाया है?

श्री सत्य नारायण सिंह : हमारी मिनिस्ट्री में सिर्फ न्यूजप्रिंट का सवाल आता है। 1968-69 के लिए जो पालिसी तय की गई है, उस के हिसाब से अखबार अपने न्यूजप्रिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यह प्रश्न हमारे यहां विचाराधीन है कि उस के सम्बन्ध में क्या करना चाहिए। अभी कोई फैसला हम ने नहीं किया है।

श्री कंवरलाल गुप्त : मन्त्री महोदय को मालूम है कि दैनिक और दूसरे समाचारपत्र कुछ लोगों की मानोपली हो गये हैं और कुछ बिजिनेस हाउसिज उन को कंट्रोल करते हैं। क्या उस मानोपली को खत्म करने के लिए मंत्री महोदय न्यूजप्रिंट को दूसरे छोटे-छोटे अखबारों को देने की व्यवस्था करेंगे?

श्री सत्य नारायण सिंह : माननीय सदस्य ने देखा होगा कि हम ने छोटे अखबारों को भी बहुत तरह की सुविधायें दी हैं। उन की प्रतियों के हिसाब से हम न्यूजप्रिंट के सम्बन्ध में उन्हें वेटेज दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि आईन्दा भी ऐसे अखबारों की मदद की जाये। जहां तक मानोपली को खत्म करने का प्रश्न है, उस के लिये यही कोई रास्ता नहीं है। हर एक आदमी चाहता है कि मानोपली खत्म करनी चाहिए। लेकिन वह कैसे खत्म हो, इस बारे में दिक्कत हो रही है। इस सदन को बताया गया है कि प्रैस कौंसिल के सामने भी यह सवाल है। वह भी इस बारे में सोच रही है और वहां इस के लिए एक कमेटी बनी है। हम लोगों के दिमाग में पूरी तरह से यह बात है हम इस में माननीय सदस्यों का भी सहयोग चाहते हैं — कि जिस तरह से भी सम्भव हो सके, कानून बनाते वक्त कोई ऐसा इफैक्टिव तरीका निकाला जाये, जिस से मानोपली को कंट्रोल किया जा सके। हम मानते हैं कि इस सम्बन्ध में हम ने अभी तक जो कुछ किया है, उस से मानोपली कंट्रोल होने के बजाये और बढ़ती गई है। "मर्ज बढ़ता ही गया, ज्यों-ज्यों दवा की।"

SHRI NAMBIAR ; That shows the failure of ihe Government. It is a clear proof of the failure of Government that the monopoly is on the increase.

श्री तुलसीदास जाधव : डिस्ट्रिक्ट्स में जो छोटे छोटे समाचारपत्र हैं, उन्हें सरकार की तरफ से कभी एडवरटाइजमेंट्स मिलते हैं और कभी नहीं मिलते हैं। उन्हें न्यूजप्रिंट भी ठीक रीत से नहीं मिलता है। इस प्रकार के लोकल समाचारपत्रों का बहुत महत्व है, क्योंकि वे बहुत अधिक लोगों तक पहुंचते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट उन्हें न्यूज्प्रिंट और एडवरटाइजमेंट्स के बारे में ज्यादा सहूलियत देने का विचार कर रही है या नहीं; अगर नहीं, तो उस का क्या कारण है।

श्री सत्य नारायण सिंह : गवर्नमेंट इस पर जरूर विचार कर रही है। इन छोटे पत्रों और लैंग्वेज न्यूजपेपर्ज पर हम को बड़ा भरोसा है, क्योंकि उन के जरिये से देश में नेशनल

इनटेग्रेशन में बहुत मदद मिलेगी। हम सोच रहे हैं कि ऐसे कौन से तरीके निकाले जायें, जिस से उन की मदद की जाये।

SHRI S M. BANERJEE : The qnestion which was put by my hon. friend Shri Madhu Limaye was whether the newsprint which they got during the strike period which lasted for nearly 59 days was sold in the blackmarket. They did not pay any wages to the employees serving under *The Statesman*, *The Times of India*, *The Hindu* and *The Hindustan Times* and other newspapers, on the ground that they had sustained heavy losses. Our information is that by selling this newsprint in the black market or by taking out supplements they have not suffered any loss. In view of Shri Madhu Limaye's question and the information with us which I have disclosed will an investigation be ordered by a commission or a senior official or the CBI or any other central agency to find out whether they have suffered auy loss ? If they have suffered no loss, will the wages be paid to those employees who suffered on account of the lock-out.

श्री सत्य नारायण सिंह : एम्प्लाईज वाला सवाल प्रत्यक्ष रूप से हमारे पास आता नहीं है। हम ने बार बार कहा है कि अभी जो मौजूदा पालिसी थी उस के मुताबिक...

श्री स० मो० बैनर्जी : मैं यह नहीं कहता। मेरे सवाल को सुन लीजिए—

श्री सत्य नारायण सिंह : एक बात माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूँ कि इस के पहले भी लम्बे समय की स्ट्राइक्स हुई हैं, यह ठीक है कि इस बार लगभग 70 दिन के लिए स्ट्राइक हुई, इतनी लम्बी पहले नहीं हुई लेकिन 30 दिद, 34 दिन और 68 दिन तक की स्ट्राइक पहले भी हुई है और कभी भी उन का कोटा काटा नहीं गया था और जो अखबार निकलते थे उन को कोई ऐडीशनल कोटा नहीं दिया गया था। एक कदम इस बार हम ने बढ़ाया कि जो अखबार छपते रहे हैं उन को एडीशनल कोटा हम ने दिया है। अब रहा यह कि उन के उस पीरियड के कोटे को कितना काटें तो वह तो हम ने साफ कहा है कि वह सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हैं कि कितना उन्होंने कन्ज्यूम किया। अभी उस के ऊपर हम ने कोई फैसला नहीं किया है इसलिए हम कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं। It is not possible for me to make any commitment.

श्री स० मो० बैनर्जी : आप मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल बिलकुल साफ और सीधा है। मैं ने यह कहा कि हड़ताल के जमाने में जो न्यूजप्रिंट उन को मिला है, उन का कहना यह था कि उन्हें नुकसान हुआ है नुकसान की वजह से वह तनख्वाह और एलावेंसेज नहीं दे रहे हैं, पत्रकार और नान-पत्रकार बन्धुओं को, हम लोगों का कहना यह है कि अगर न्यूज-प्रिन्ट उन को मिला है और न्यूज प्रिन्ट पड़ा है कहीं कोठरी में तो कोई बात नहीं लेकिन उसे बेचा है या सप्लीमेंट्री के मार्फत बेचा है, अगर यह सही बात है तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वह पैसा मजदूरों को दिलाने की कोशिश मन्त्री महोदय श्रम मन्त्रालय से मिल कर करेंगे ?

श्री सत्य नारायण सिंह : हम लोगों की पूरी सहानुभूति तो उन के साथ है लेकिन कितना घाटा उन का हुआ है...(व्यवधान)...

श्री स० मो० बैनर्जी : इन्वेस्टीगेशन कराइए...(व्यवधान) एक दफा सत्य नारायण जी की कथा उन को सुना दीजिए, फिर देखिए वह ठीक हो जाएंगे।

श्री सत्य नारायण सिंह : वह जैसा हम ने कहा यह सब सवाल जो आप ने उठाया है यह सब हमारे सामने है कि कैसे किया जाय। इसलिए कोई आखीरी फैसला अभी मैं नहीं बता सकता। लेकिन हम लोगों के दिल में यह जरूर है कि स्ट्राइक वाले पीरियड में सचमुच में न्यूज-प्रिन्ट कोटा मिला है तो हम लोग उस पर क्या कर सकते हैं। यह हम से मेहरबानी कर के अभी कबूल मत करवाइए कि हम क्या करने जा रहे हैं।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि उन का ध्यान इस तरफ आकृष्ट किया गया है कि इन पत्रों को जो कोटा उन के मन्त्रालय से सिफारिश होता है उस कोटे के मुताबिक जो एस० टी० सी० के तहत विदेश मंत्रालय उन को परमिट देता है और उस परमिट से जो कागज आयात होता है उस में व्यापार तरीकों के खिलाफ, कानून के खिलाफ और नीति के खिलाफ तीन प्रति शत काला बाजार होता है और उस काले बाजार को रोकने में न मन्त्री महोदय का मंत्रालय मदद कर सकता है और विदेश व्यापार मन्त्रालय कहता है कि यह व्यक्तिगत स्वरूप का करार है हालांकि ऐसा नहीं है और विदेश आयात कानून के अन्तर्गत इस काले व्यापार को रोकने के लिए कोई छोटा अखबार वाला अदालत में भी नहीं जा सकता है तो एक तरफ अदालत में जाने से रुकावट एक तरफ विदेश मंत्रालय, विदेश व्यापार मन्त्रालय का उस में हाथ और दूसरी तरफ एम०टी०सी० की असमर्थता, तो ऐसी स्थिति में क्या मन्त्री महोदय का ध्यान इस तरफ आकृष्ट हुआ है और क्या वह छोटे अखबार वालों को कोई मदद करने की बात सोच रहे हैं ?

श्री सत्य नारायण सिंह : अभी माननीय सदस्य ने स्वयं बताया कि कितना कठिन काम है कि तीन-तीन मंत्रालय मिल कर लगे हुए हैं और कोई रास्ता निकलता नहीं है तो आप कैसे समझते हैं कि हम अभी कोई रास्ता आप को बता दें ? कितना मुश्किल काम है ?

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : करोड़ों रुपये का काला व्यापार होता है ।

SHRI J. H. PATEL : I would like to draw the Minister's attention to the 12th Annual Report of the Register of Newspapers, p. 8 where he has specifically stated :

> "Small newspapers numbering 1135 representing 83.2 per cent of the applicants availed only 8.7 per cent of the newsprint. Big papers (73) consumbed 66.1 per cent and medium (156) consumbed 25 per cent".

This clearly shows that this Government shows some discrimination in favour of big papers as against small papers. This is one kind of discrimination. That is the kind of discrimination this Government shows favouring the English newspapers as against the language papers. From page 70, Table IV of this book we find that there are only 1843 papers published in English as against 8640 papers published in our languages. There is not even one-tenth. According to this report, thirty per cent of the newsprint had been allotted to such English newspapers. May be they are more in circulation. But the point is that they have shown a specific favour to English newspapers as against the languages papers whether dailies, weeklies or monthlies. Why should they show such discrimination ? Why should they show discrimination in favour of big papers against small newspapers ?

SHRI SATYA NARAYAN SINHA : I do not think that we are making any discrimination. We shall examine the point made by him when we decide about the policy next year. But so far, I do not think there has been any discrimination. If some papers get more, it is because their circulation may be more... *(Intrupptions)* I said that we should take into account all relevant factors when deciding the policy for the next year.

श्री शिव नारायण : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को बड़ी खुशी है कि हमारे नये इन्फार्मेशन मिनिस्टर इस हाउस के सब से पुराने मेम्बर हैं । उन से हम लोग चाहते हैं कि वह उन गरीब वर्करों को पूरा एश्योरेंस दें और इस मोनोपली को कंट्रोल कर के उन के वेजेज दिलाने की कृपा करें । क्या वह इस के लिये आश्वासन देंगे ?

श्री सत्य नारायण सिंह : इस के लिए हम ने कहा कि उस के बारे में हम लोगों से जो हो सकेगा करेंगे । अभी क्या कहूं ? बार-बार मैं ने कहा कि अभी हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं ।

एक माननीय सदस्य : कब कहेंगे ?

श्री सत्यनारायण सिंह : जब काम होगा तो आप को पता चल जायगा।

SHRI NATH PAI : Inspite of the many protests repeated here by the hon. Minister, the conclusion is irresistible that this Government is discriminating against small papers be it through newsprint quota or be it through the taxation policy of his senior colleague. They are slowly seeing, for reasons best known to themselves, that the small and medium newspapers are slowly driven to death. He will again protest and I do not except a reply from him. In view of the fact that nearly 16 per cent of the quota for the big newspapers was saved last year as a result of the strike which continued for 59 days during which the total impotence of this Government was exhibited for the whole nation to see, will the Government take into consideration while allotting their quota for this year the fact that there was a saving of about 16-17 per cent of the quota which was made available to them?

SHRI SATYA NARAYAN SINHA : We shall take that into consideration; I have already said so We shall keep this in view when we make allotment for 1969-70.

श्री सु० कु० तापड़िया : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर कुछ प्रश्न और उन के माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर सुन कर मेरे मन में भी कुछ भ्रम हो गया और मन्त्री महोदय से मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या हमारे देश में कोई ऐसा कानून है कि जो समाचारपत्रों को सप्लीमेंट छापने में या उस में अधिक विज्ञापन लेने या उस के द्वारा मुनाफा कमाने से रोकता है ? यदि ऐसा कानून और व्यवस्था है कि जो रोकता है तो आप बताने की कृपा करें।

श्री सत्य नारायण सिंह : कानूनी व्यवस्था तो इस के सम्बन्ध में कुछ है नहीं।

———

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Rubber Plantation in Kerala

*424. SHRI S.K. TAPURIAH : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) the details of the programme, if any drawn up for the development of the rubber plantations in Kerala under the Fourth Five Year Plan' indicating the outlays for each scheme under the programme and the targets of production of natural rubber to be achieved thereunder;

(b) the assistance proposed to be given by Government for its implementation;

(c) whether in view of the acute shortage of rubber in the country, Government have any scheme for giving special aid or incentives for expansion or development of rubber plantations; and

(d) if so, the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) to (d). Under the Fourth Five Year Plan, programmes have been drawn up for the development of rubber plantations on an all India basis including Kerala State. The target proposed for production of natural rubber at the end of the Fourth Five Year Plan period 1973-74 is 1,25,000 tonnes. The Rubber Board has proposed various programmes and outlays. The matter is under consideration

Expansion of Electronics Industry

*425. SHRI K.P. SINGH DEO : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to extend certain facilities to entrepreneurs to expand their capacity in the electronics industry and to instal new plants for the manufacture of electronic components; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI L.N. MISHRA) : (a) and (b). Yes, sir. Certain facilities are being extended to entrepreneurs to expand their capacity in the electronics industry and to instal new planst